

सम्पादकीय

आपातकाल की 50वीं बरसी....

देश 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी मना रहा है। मोदी सरकार आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिये आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है तो दूसरी ओर राजनेता हों या मीडियाकर्मों अथवा सामान्य जन, सभी उस दौर को याद कर काग्रिस को कोस रहे हैं क्योंकि वह देश की सरकार द्वारा अपनी ही जनता पर किये गये अत्याचार की निर्मम पराकाष्ठा थी। उस समय देश में एक लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में दंस दिया गया था। देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। राजनीतिक बंदियों की अपने परिवारों से मुलाकात तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेता ही नहीं अदालतें भी एक तरह से तंके हो चुकी थीं। किसी को जमानत नहीं दी जा रही थी और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। राजनीतिक कार्यकांत जेल में मानसिक-शारीरिक यातनाएं सह रहे थे। पुलिस हिरासत और जेलों में मौत हो रही थी लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। हम आपको बता दें कि देश में आपातकाल के 1975 में अधिकारिक रूप से लागू होने से पहले, ग्रामीण इलाकों में छोटे बच्चे अक्सर बिना कपड़ों के फकिरी से डूँड़ते-भागते नजर आते थे। लेकिन आपातकाल के दौरान हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोगों ने मासूम बच्चों को भी कपड़े पहनाने शुरू कर दिए थे, यह शालीनता की भावना से नहीं हो रहा था बल्कि जबरन नसबंदी की आशंका से उपजा डर था, जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया था। सामूहिक नसबंदी अभियान की यादें आज भी जीवित बचे पीड़ितों को परेशान करती हैं क्योंकि कई लोगों की नसबंदी जबरदस्ती की गई थी। अकेले 1976 में, पूरे भारत में 80 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी। इसमें से ज्यादातर पुरुष थे, जिसमें से कई लोगों की नसबंदी स्वीच्छक नहीं थी। हम आपको बता दें कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तानाशाह इसलिए बन गयी थीं और देश पर आपातकाल इसलिए थोप दिया था क्योंकि एक पुराना मामला राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन गया था। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव में तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आरोपों में संधी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया तथा इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राज नारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। अदालत के इस फैसले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंशतः रद्द कर दिया। उन्होंने दलील दी थी कि इंदिरा गांधी ने अपने रहने की इजाजत दे दी। इस फैसले से विपक्ष में जहां नया जोश आ गया वहीं इंदिरा गांधी बौखला गयी थीं। अपने खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की रात को आपातकाल लगाने का फैसला किया और रात्रि को ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दे दस्तखत के साथ भारत में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह सप्मू देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को आपातकाल का मतलब तब समझ आया जब उन्हें पता चला कि उनके सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे जनता नाराज हुई और सड़कों पर उतरने लगी लेकिन सड़क पर उतरने वाले हर शख्स को जेलों में दंस दिया गया था। हम आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में कुल 48 अध्यादेश लागू किए थे जिसमें आंतरिक सुरक्षा कानून अधिनियम (मीसा) में संशोधन के लिए लागू गए पांच अध्यादेश भी शामिल थे। प्रशासन को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देने वाले इस कानून को अक्सर दमनकारी कानून की संज्ञा दी जाती है।

जयंती

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय

जन्म : 26 जून, 1838; मृत्यु : 8 अप्रैल, 1894)
19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकाण्ड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देश भक्ति कि वन्देमातरम की रचना की जिसे बाद में आनन्द मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। प्रसंगः गायब्व है कि वन्देमातरम गीत को सबसे पहले 1896 में काग्रिस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।

पुण्यतिथि

गोविंद शास्त्री दुगवेकर

मृत्यु-26 जून, 1961 ई., जबलपुर, मध्य प्रदेश)
हिन्दी भाषा और साहित्य के अन्य सेलक तथा बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कृतिकार थे। 'भारतेन्दु नाटक मण्डली' के रूप में श्राद्ध सूत्र-हिन्दी-रंगमंच की सर्वप्रथम स्थानाना में गोविंद शास्त्री जी का प्रमुख हाथ था। गोविंद सन 1901 ई. के आस-पास काशी चले आये थे और जीवन के शेष 60 वर्षों में अधिकांशतः काशी में ही रहकर साहित्य सामान की। ये केजभाषा तथा खड़ीबोली में बड़ी ही उत्कृष्ट कविता करते थे। बाल-साहित्य के अभाव की पूर्ति के लिए गोविंद शास्त्री ने चित्र-कथा के रूप में बहुत सी कहानियाँ भी लिखी है।

कल मिलेंगे

टीसर स्टूडेंट से-ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट-चिड़िया बनकर.
टीसर-तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? स्टूडेंट-जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा..

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रूद्रावतार हनुमान जी (मैंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-28।सी, गली नं० 3, ए-प्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एन्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI NO. : DELHN/2016/70240
Phone NO. : 9871221635
E-mail ID : sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

विचार

आपातकाल: अधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

—**डॉ. आशीष वशिष्ठ**

50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश इस फैसले से भौंचक रह गया। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। आपातकाल लगाया गया, जो मार्च 1977 तक चला। इस दौरान भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया और एक तानाशाही शासन की शुरूआत इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और आम नागरिकों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और हत्या तक की गई। इस दौर में संविधान को भी कमजोर किया गया। हालांकि, आपातकाल का हर पहलू चौंकाने वाला था, लेकिन खासकर छात्रों पर किए गए अत्याचार बेहद निंदनीय थे। सब कुछ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए।

पहली बार ऐसा मौका था जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। लोगों को आपातकाल के मतलब भी नहीं पता था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आम जनता के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी तरह की अभिव्यक्ति को आजादी का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। आम जनता, मीडिया समूह, रेडियो, और अन्य प्रचार के माध्यमों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर की प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। आपातकाल की सूचना के बाद से ही देश में दूढ़-दूढ़ कर विपक्ष के नेताओं की

यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय विचार और भारतीयता के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर

भारतीय संसदीय इतिहास के काले अध्याय के 50 साल

—**आचार्य डॉ राधेश्याम द्विवेदी**

आपातकाल क्या है?—यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, को देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।

50 साल पहले क्या थी परिस्थितियां: मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है।

संसद में भारी बहुमत की सरकार रही: 1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री के

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल उस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में दंस दिया गया

गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। तत्कालीन समय के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के विपरीत विचारधारा वाले सभी लोगों और आम जनता में बेगुनाहों को भी जेल में भर दिया गया था, जेलों में जगह नहीं बची थी। करीब 1,40,000 लोगों आपातकाल में बिना किसी सुनवाई के राजनीतिक बंदी बनाया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल के दौरान पूरे देश का नियंत्रण गांधी-नेहरू परिवार के हाथ में था। कांग्रेस ने आपातकाल की आड़ में वो सभी काम किए जो ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से अशोभनीय थे बल्कि अमानवीय भी थे। प्रेस में सरकार या आपातकाल की आलोचना करना अपराध की श्रेणी में आ चुका था। प्रेस-मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किया गया था। हालात यह थे कि कांग्रेस समर्थित उस अधिकारी के अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी हो रही थी।

यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय विचार और भारतीयता के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर

12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था

सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा 6 साल के लिए बेदखल: 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी जी के अपील पर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी

पर बने रहने की इजाजत दी।11975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

25 जून 1975 को आपातकाल घोषित: इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई।

21 महीने रहा थे काला आपात काल: 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।

आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकत**ा था:** 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

प्रेस पर सेंसरशिप: 1975 के आपातकाल के दौरान, सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया,

आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल उस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में दंस दिया गया। विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने गोलियां भी चलाईं। चार लोगों की जान चली गई।

संजय गांधी की सनक के चलते सड़क से भिखारियों, झोपड़पट्टी के लोगों और राहगीरों को पकड़ कर जबरन नसबंदी के टारगेट पूरे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को नसबंदी अभियान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी थी। जिसमें 42 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। मृतकों की स्मृति में यहां शहीद चौक बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान देशभर में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी।

21 महीने के बाद जयप्रकाश का आंदोलन निर्णायक मुकाम तक जा पहुंचा। इंदिरा गांधी को

सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 में आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को जानने के लिए जस्टिस जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन गठित किया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई उस वक्त ना देश में आर्थिक हालात खराब थे और ना ही कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी इच्छा के अनुसार लगाया था और इस संबंध में उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों को छोड़कर किसी भी सहयोगी से कोई विमर्श नहीं किया था।

आपातकाल में गिरफ्तार किए गए अधिकतर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी, जो उन्हें अस्पताल में मौजूद नहीं कराई गईं। इंदिरा गांधी की तानाशाही का एक नमूना इस बात से भी पता चलता है कि शाह आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैए की बेहद आलोचना की थी। आयोग ने कहा था कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की जबरदस्ती नसबंदी की गई इसके साथ-आँटो रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना था कि सरकारी तंत्र का उपयोग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे आपातकाल का इस्तेमाल किया गया।

जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि वर्ष 1975

में आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरज डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल किया था कि जीने का अधिकार स्थगित है। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र 1 अगस्त 1977 में संसद में पेश किया गया। सत्या सी पेज के श्वेत पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि तानाशाही की इच्छा रखने वाली इंदिरा गांधी ने अपनी अध्यक्षता में तय किया था कि प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन चारों समाचार एजेंसियों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जिससे उन्हें संसर करने और संभालने में आसानी होगी।

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता पिछले कुछ समय अक्सर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। संसद से सड़क तक वे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि उनकी पार्टी के नेता ने दादागिरी करके इस देश पर 21 महीने आपातकाल लगाकर लोगों को जेल में दंस दिया था। असल में, 1975 में लगाया हुआ आपातकाल इंदिरा गांधी की गलती नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी का "अहंकार" था। दिसंबर 2024 को सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का उल्लेख किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी यह कलंक मिट नहीं सकेगा क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारतीय संविधान निमाताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत कुख्याति मिली थी।

संविधान का दुरुपयोग: आपातकाल लगाने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नागरिकों के नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिससे सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति मिल गई।

मीसा और डीआईआर का दुरुपयोग: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निगम (डीआईआर) जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया गया ताकि लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें हिरासत में लेने का संकेत मिले।

लोकतंत्र का दमन: आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया और सरकार की आलोचना करने वाली आवाजें दबा दी गईं। आपातकाल के दौरान हुई इन मनमानीयों के कारण, इसे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का फिर से किया दावा

(एजेन्सी)। **अमेरिका।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया और दोनों देशों से कहा कि यदि वे लड़ाई जारी रखेंगे तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। चार दिनों तक झूठे और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य टकराव रोकने

पर सहमत हुए। ट्रंप ने नीदरलैंड के हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार को लेकर कई बार फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने कहा, देखिए, अगर आप एक-दूसरे से लड़ते हैं... यह बहुत बुरा हो रहा था, आप जानते हैं कि पिछला

हमला कितना बुरा था। यह वास्तव में बहुत बुरा था। ट्रंप ने कहा, अगर आप एक-दूसरे से लड़ते हैं, तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह एक महान इंसान हैं। मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा, अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे...और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं

आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकत

आ एक रूसी संघ परिषद की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। वार्षिक अख्यलायन रीडिंग्स भारत सहित 40 देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विषय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों की एक बैठक है। हाल में एक

बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए थरु ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई के संबंध में भारत का रुख बताने के लिए अमेरिका और चार अन्य देशों का दौरा किया था।

अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाशि कपूर, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के इष्टलीकेट (हमशकल) थे। अपने विवादास्पद विषय के कारण फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक माहौल बदलने के बाद 1978 में इसे रिलीज किया गया।

6) क्रांति की तरंगें आनंद पटवर्धन द्वारा बनाए गए पहले वृत्तचित्र में बिहार में जेपी आंदोलन का शुरूआत और 1975 में जब यह आपातकाल लागू होने से पहले यह कैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, इस पर बात की गई थी। आनंद ने 1975 में जब यह फिल्म बनाई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और उन्होंने उस समय जन आंदोलन और नागरिक अशांति को दिखाया था, जब मुख्यधारा का मीडिया सरकार के बढ़ते दबाव में था। आपातकाल के दौरान चोरी-चुपके व्यापक रूप से इसका प्रसार किया गया था।

केशव प्रसाद मोर्य ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का दिया संदेश



संजना भारती संवाददाता मनोज कुमार बिन्दु
प्रयागराज। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपातकाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ आपातकाल पर आधारित संगोष्ठी से हुआ, जिसमें आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव और लोकतंत्र पर उसके नकारात्मक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर आपातकाल पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से उस कालखंड की चुनौतियों और उससे मिले सबक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर आपातकाल पर आधारित एक संक्षिप्त प्रदर्शनी (एजीबिशन) भी लगाई गई, जिसमें उस समय की प्रमुख घटनाओं,

संघर्षों, विरोध, समाचारों और दस्तावेजों को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया। सभी उपस्थित जनों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शनी से लोकतंत्र में आपातकाल की त्रासदी से सबक लेने हेतु जागरूकता व प्रेरणादायक पहल बताया।

इस अवसर पर मा0 उपमुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आपातकाल एवं उससे जुड़ी त्रासदी एवं विषयवस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हम ईमानदारी और सवेदनशीलता से निभाएं। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में लोकतंत्र व संविधान के दृष्टि से काला दिन बनकर अंकित है। उन्होंने कहा कि 1975 के आपातकाल में भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल थोप कर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का दमन किया गया था और पत्रकारिता को प्रतिबंधित करने, न्यायपालिका के अधिकार सीमित करने

एवं विपक्ष के नेताओं को जेल में कैद करने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही लोग अपनी इच्छानुसार स्वार्थवश लागू किये गये आपातकाल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होंगे और आज की पीढ़ी को इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष से संविधान की रक्षा का कार्य नहीं किया होता, तो हमारे पास मताधिकार का भी अधिकार नहीं होता। वर्तमान सरकार संविधान के मूल्यों की रक्षा व मजबूत करने के प्रति दृढ़संकल्पित एवं देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की गयी है और अब कभी भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने नहीं दिया जायेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने नहीं दिया जायेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मा0 उपमुख्यमंत्री

जी ने लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मा0 सांसद फूलपुर श्री प्रवीण पटेल, मा0 महापौर श्री उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ0 वी0के0 सिंह, मा0 विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल, मा0 विधायक फाफामऊ श्री गुरु प्रसाद मोर्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापर अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान, यमुनापर अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला सहित अन्य मा0 जनप्रतिनिधिगण, लोकतंत्र सेनानियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोक उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री जी ने जिला पंचायत परिसर में वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के अन्तर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपित किया और पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी श्री अरविंद कुमार यादव एवं जिला वृक्षारोपण समिति के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नशा व एचआईवी/एसटीआई जागरूकता शिविर का आयोजन, 55 लोगों का हुआ टेस्ट

बस स्टैंड करनाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सराहनीय पहल

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन के मार्गदर्शन में बस स्टैंड करनाल पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नागरिकों को नशे से बचाव और एचआईवी/एसटीआई से सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।

शिविर में सिविल अस्पताल की काउंसलर डॉ. कांता रानी, ममता और पैरा लीगल वॉलंटियर पूजा ने भाग लिया। डॉ. कांता रानी ने बताया कि एचआईवी/एसटीआई की जांच, काउंसलिंग और इलाज सिविल अस्पताल में पूरी तरह नि:शुल्क व गोपनीय तरीके से किया जाता है। उन्होंने संक्रमण के प्रमुख



कारणों की जानकारी देते हुए कहा कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सिरिज का प्रयोग, असुरक्षित रक्त चढ़ाना तथा

लिए निरंतर कंडोम के उपयोग, केवल स्वच्छ व लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक से रक्त लेने तथा सुई-सिरिज के प्रति सतर्कता जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एचआईवी का संक्रमण छूने, साथ घटने-बैठने, गले लगने, रिवॉर्मिंग पूल या शौचालय के साझा उपयोग से नहीं फैलता।

पैरा लीगल वॉलंटियर पूजा ने जानकारी दी कि यदि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह एचआईवी एक्ट 2017 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के तहत पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता भी प्राप्त हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषियों को दंड व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। शिविर के दौरान सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम द्वारा कुल 55 लोगों के एचआईवी टेस्ट किए गए।

वेद में सूर्य चंद्र और गुरु का महत्व अति विशिष्ट है: चिदात्मन जी महाराज

एसबी ब्यूरो बीहट/बेगूसराय। सिद्धाश्रम सिमरिया से गोविंद हरे गोपाल हरे जय घोष के साथ रथ यात्रा के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों की टोली पूरे सिमरिया धाम क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए द्वादश कुंभ स्नान बनाने के लिए राम जानकी घाट पर पहुंचे,वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल उत्स है। श्री राम राज्य में वैदिक संपदाओं के कारण किसी प्रकार का भय नहीं था। वेद में सूर्य चंद्र और गुरु का महत्व अति विशिष्ट है इसलिए एक राशि प्रयोग में प्रकृति में अति विशिष्ट आ जाती है। जल जीवन का आधार है जो विशेष अमृत तत्व को प्राप्त करता है तत्वदर्शियों से लेकर विद्वान नेताओं तक सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि सूर्य ही जगत की आत्मा है। सूर्य से ही ब्रह्मांड उत्पन्नित है। भारत का इतिहास अरबों वर्ष प्राचीन है मंत्र, तीर्थ, देव, द्विज संतों में भावना का ही प्रधानता है। शास्त्र अनुसार 12 राशियों पर सूर्य एक-एक महीना रहते हैं



जिसे शौर्य मांस यानी की संक्रांति कहते हैं और चंद्रमा का समय लगभग ढाई दिनों तक रहता है। बृहस्पति प्रत्येक राशि पर एक वर्ष रहते हैं जब एक ही राशि पर इन तीनों का योग होता है। तो वह शास्त्र अनुसार कुंभ योग कहलाता है यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद इस राशि पर पहुंचता है। रुद्राया मलोक अमृतिकरण प्रयोग में वर्णित है। जैसे मेष की संक्रांति में हरिद्वार उज्जैन वैशाख महीना में ज्विज की संक्रांति में बद्रीनाथ धाम में ज्येष्ठ महीना में मिथुन की

संक्रांति में जगन्नाथ धाम आषाढ़ महीना में कारक की संक्रांति में द्वारिका पुरी सावन मास में सिंह की संक्रांति में नासिक में भादवा माह में कन्याओं की संक्रांति में रामेश्वरम आसीद मास में तुला की संक्रांति में सिमरिया धाम कार्तिक महीना में वृश्चिक की संक्रांति में कुरुक्षेत्र अगहन महीना में धनु की संक्रांति में गंगासागर पोस्ट महीना में मकर की संक्रांति में प्रयाग माघ महीना में पुरुष की संक्रांति में कुंभ को फाल्गुन महीना में आसीन की संक्रांति में

ब्रह्म कुंड चैत्र महीना में, राजा हर्षवर्धन के सौजन्य से इनमें से लुज कुंभ योग प्रयास पुनः आरंभ हुआ परंतु उनकी राज सीमा में ही सिमट कर रह गया जिसमें आज चार जगह का कुंभ मेला विख्यात है।

हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक इसलिए जी लोग आज के कुंभ योग में जगन्नाथ धाम में स्नान नहीं बना सके वह श्रद्धालु किसी कारण बस जगन्नाथ पुरी नहीं पहुंच सके वह द्वादश नाम से प्रसिद्ध मिथिला में द्वादश कुमार बनाकर जीवन सफल बना लिए। मौके पर रविन्द्र ब्रह्मचारी, दिनेश प्रसाद सिंह, मोडिया प्रभारी नीलमणि, नवीन सिंह, डॉ. धनश्याम झा, डॉ.विजय झा, सत्यानंद, तरुण कुमार, विपिन कुमार, आचार्य नारायण झा, पंडित रमेश झा,राम झा, श्याम झा, लक्ष्मण झा, संजय सिंह, पवन कुमार, निपेनदर सिंह, पप्पू त्यागी, गौरी शंकर सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे।

शिक्षिका के स्थानांतरण पर विद्यालय में विदाई समारोह का हुआ आयोजन

एसबी ब्यूरो मंसूरचक(बेगूसराय)। बुधवार को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सहनी टोल गणपतोल बीपीएससी शिक्षिका रिचा कुमारी को प्रभारी प्रधानाध्यापक अशर्मा पासवान के द्वारा रिचा कुमारी के स्थानांतरण के फल स्वरूप विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें अन्य शिक्षकों के द्वारा जैसे अंकित सिंह मो. कैसर अंसारी, चंद्रजित यादव एवं रसोईया कर्मी एवं विद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वारा श्रीमती रिचा कुमारी को दूसरे विद्यालय के योगदान के लिए सम्मानित करते हुए भेजा गया। रिचा कुमारी सभी बच्चों से भावुक होकर उनकी आंखें नम हो गई लगभग उनको 2 साल विद्यालय में बच्चों के साथ हिल मिलकर लगन से पठन-पाठन करवाता। इनका स्थानांतरण छोटी बलिया बेगूसराय में अपने निकटतम ग्राम उत्कर्मित उर्दू मध्य विद्यालय सालोहचक हुआ।



धान की सीधी बिजाई से 35% तक घटेगा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन: डॉ. प्रमोद तोमर

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। बासमती धान की सीधी बिजाई तकनीक (डी.एस.आर.) न केवल पानी की बचत करेगी बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी 30 से 35 प्रतिशत तक की कमी लाएगी। यह जानकारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अंतर्गत कार्यरत बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ), मोदीपुरम-मेरठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद तोमर ने दी। वे करनाल के सेक्टर-12 स्थित जाट भवन में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला में किसानों को संबोधित कर रहे थे।

इस कार्यशाला का आयोजन एचएफपीसी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एफ.पी.ओ.) की ओर से किया गया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

डॉ. तोमर ने बताया कि जब पंजाब और हरियाणा में लेबर और पानी की किल्लत महसूस हुई, तब डी.एस.आर. तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी आई। यह तकनीक 25 से 30 प्रतिशत तक जल की बचत करने में सक्षम है। साथ ही यह बकानी रोग की संभावना को भी कम करती है। उन्होंने कहा कि एक किलो चावल के उत्पादन में औसतन 3000 लीटर से अधिक पानी की खपत



होती है। यदि खेत को लेजर लेवलिंग से समतल किया जाए, तो पानी की बचत और भी बेहतर ढंग से की जा सकती है। परंपरागत रोपाई में 5 से 6 इंच तक पानी खड़ा किया जाता है, जबकि डी.एस.आर. में यह आवश्यकता काफी कम हो जाती है।

डॉ. तोमर ने डी.एस.आर. के तहत तरबतर विधि (पंजाब में प्रचलित) और सूखी बुआई (हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित) के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि बासमती धान की दो प्रजातियां डी.एस.आर. के लिए विशेष रूप से अनुशंसित की गई हैं और 35 दिन पर खेत में पाटा प्रैक्टिस करनी चाहिए।

कार्यशाला में किसानों को मित्र कीटों और शत्रु कीटों की पहचान, प्राकृतिक

कीट प्रबंधन विधियां तथा रसायन मुक्त खेती के टिप्स भी दिए गए। डॉ. तोमर ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात में गुणवत्ता का विशेष महत्व है और यदि उसमें पैस्ट्रीसाइड के अंश पाए जाते हैं, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग प्रभावित होती है। पिछले वर्ष देश से 7 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हुआ जिससे 50 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उचानी- करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ओ.पी. चौधरी ने एफ.पी.ओ. की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और किसानों को घरेलू खपत के लिए सब्जियां व फल उगाने की सलाह दी। डॉ. आलोक मुखर्जी, निदेशक, रिसर्च एनालिटिक्स एंड

मॉडलिंग, लीड्स कनेक्ट प्रतिष्ठान, ने सेटेलाइट आधारित "शतशती पोर्टल" का अनावरण किया और बताया कि कैसे यह पोर्टल फार्म स्तर पर ए.आई. आधारित निर्णय प्रणाली में सहायक होगा। एफ.पी.ओ. के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. मलिक ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जबकि उपाध्यक्ष डॉ. एस.पी. तोमर ने जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और शुद्ध बासमती उत्पादन पर व्यावहारिक जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनुज कुमार, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह, नाबार्ड के ए.जी.एम. हिमांशु खत्री, निफको नीलोखेड़ी के चेयरमैन डॉ. सरदार सिंह समेत कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

गुरुकुल में मार्गदर्शन की भूमिका पर सेमिनार आयोजित, शिक्षकों को मिला प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम



एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलह, परामर्श व कल्याण केन्द्र के अंतर्गत आज गांव मोर माजरा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल (परामर्श केन्द्र संख्या-136) में "गुरुकुल में मार्गदर्शन की भूमिका : प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का मिश्रण" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहकव व राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि

मेंटरशिप एक ऐसा संबंध है, जिसमें अनुभवी व्यक्ति अपने ज्ञान व अनुभवों को कम अनुभवी लोगों से साझा करता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु-शिष्य संबंध मार्गदर्शन का मूल आधार रहा है, जो विश्वास, सम्मान और संवाद पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का मिश्रण आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रभावी बनती है, बल्कि छात्रों को डिजिटल साक्षरता और व्यवहारिक कौशल भी मिलते हैं। शिक्षक को यह विश्वास रखना चाहिए

कि उनका कार्य देश निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। सेमिनार में परामर्शदाता नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षकों व अभिभावकों को बच्चों के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए और एक ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए।

कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्षता गुरुकुल अध्यक्ष सुखबीर सिंह मान व प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत लाभकारी होते हैं। इस अवसर पर आर्य

कन्या कॉलेज प्रिंसिपल सदीप खंडवाल, ओमप्रकाश, विजेंद्र मोर, बाल कल्याण परिषद की अधिकारी सुमन शर्मा, अजीवन सदस्य नीरज कुमार, मनीष व अंकित विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश गया कि आज के बदलते समय में गुरुकुलों को प्राचीन शिक्षण परंपराओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, ताकि छात्राएं न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनें, बल्कि बचपन के सर्वांगीण विकास में अत्यंत हो सकें।

आपातकाल के 50वां वर्ष पूर्ण होने पर मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम आयोजित



एसबी ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन बदायूं। आपातकाल के 50वां वर्ष पूर्ण होने एवं आपातकाल दिवस के अवसर पर जिला गोष्ठी व लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने मां सस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोष्ठी से पहले प्रभारी मंत्री

गुलाब देवी व अन्य जनप्रतिनिधियों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाकर वृक्षारोपण किया। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा स्वाधीनता आंदोलन के नायक अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मोहनर जोशी आदि नेता जेल में थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975-77 भयावह था। आपातकाल लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था।

जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को मनाया जा रहा है। सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा आपातकाल के दौर को नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। पूर्व विधायक व लोकतंत्र सेनानी प्रेमस्वरूप पाठक ने कहा आज हम देश की युवा पीढ़ी को यह

बताना चाह रहे हैं कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत था। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी रामकिशोर, लोकतंत्र सेनानी सरोज, दावागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, शैलेंद्र मोहन शर्मा, एमपी सिंह राजपूत, धीरज पटेल, आशीष शाक्य, डॉ अमित गुप्ता, डॉ ऋतुज, डॉ वैकटेश, डॉ मुरतयाक सहित बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

इतिहास पर आपातकाल का धब्बा, देशवासी नहीं करेंगे माफ: डॉ अरविंद शर्मा

■ 'आपातकाल से अछूती युवा पीढ़ी को हकीकत से रूबरू कराना जिम्मेदारी'



एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और इसके गौरवशाली इतिहास पर आपातकाल गहरा धब्बा था। लोकतंत्र की निर्मम हत्या और ऐसी विभिषका से जहां लोकतंत्र सेनानी व उनके परिवार आज तक नहीं उभर पाए हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे और इस हकीकत से अछूती युवा पीढ़ी को उनके संकल्प, साहस से रूबरू कराया जाए।

बुधवार शाम को अग्रसेन धर्मशाला, कैथल में आपातकाल के काले अध्याय से 50 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने जिला के लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। गणमान्य नागरिकों की संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं को अपने में समेटने वाला हमारा देश भारत दुनिया में विश्वगुरु के

तौर पर अपनी पहचान रखता है। हमारा गौरव शाली इतिहास रहा है। जिसमे अनेकों ऐसे अवसर है। जिन्हे याद कर सीना चौड़ा हो जाता है।

उन्होंने कहा कि इसी बीच 25 जून 1975 की काली रात में देश में लोकतंत्र की निर्मम हत्या की गई थी। उस विभिषिका से हमारा देश आज भी नहीं उभर सका है। 50 साल पहले, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में घृणित आपातकाल का घृणित अध्याय जोड़ा गया था। वह वो दिन थे, जो इतिहास में दर्ज ही नहीं हुए, बल्कि देश, देशवासियों की आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गए। सत्ता के मद में चूर कांग्रेस सरकार ने रात के सन्नाटे में आपातकाल लागू करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया था। उन्होंने कहा कि यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह उस आत्मा पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देती है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के इतिहास का काला दौर था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना

अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ज़िद और अहंकार के चलते देश के एक लाख 11 हजार लोगों को आपातकाल की आड़ में जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे महान नेताओं को जेलों में डाला गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, न्यायपालिका को बेबस बनाया गया और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के इन 21 महीनों में देश के नागरिकों ने न केवल असहनीय पीड़ा झेली, बल्कि अनेकों जघन्य अपराध होते देखे। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो 24 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने लाखों देशवासियों की भांति तत्कालीन सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की धरती भी इस संघर्ष में पीछे नहीं रही। यहां किसी ने जेल की सजा काटी, किसी ने अपने परिवार और करियर को चिंता किए बिना संविधान की रक्षा को सर्वोपरि रखा। आज जब हम उन

सेनानियों को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं, तो यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारे समर्पण की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने से लेकर दुश्मनों से देश की सुरक्षा करने के ऐतिहासिक उदाहरण जनता को दिए हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक -एक विधान के सपने को साकार करने की बात हो या आप्रेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद व आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया सुनिश्चित करना, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की इसी चेतना और सतर्कता को जीवित रखने के लिए भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य किया है। समय-समय पर उनके परिजनों को सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित किया गया है, और उनके गौरवपूर्ण संघर्ष को सराहने हेतु विशेष योजनाएं भी शुरू की गई हैं। वर्ष 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के

बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इमरजेंसी के दौरान जेल जाने और असहनीय कष्ट सहने वालों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने की परंपरा को शुरू किया व उन्हें लोकतंत्र सेनानी के तौर पर सम्मान दिया। वर्ष 2016 में ऐसे 891 लोगों को चिन्हित करके ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में शुभ ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को पेंशन देने 10 हजार रूपए मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। उनके लिए हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा व वोल्टो बसों में 75 प्रतिशत किराया माफ किया गया। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन को 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 20 हजार रूपए किया है। हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्मृति और प्रेरणा का हिस्सा बने। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मदन गोयल व नेपुण डाबला रहे।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, विधायक सतपाल जांबा, जिला प्रभारी अमरपाल राणा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, कुलवंत बाजीराम, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर व मुनीष कटवाड़, नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, कार्यक्रम संयोजक अमरजोत छाबड़ा, सुभाष हजवाना, श्याम सुंदर बंसल, बलजिंदर जांगड़ा, सुरेश संधु, भीम सैन अग्रवाला, शैली मुंजाल, कृष्ण मित्तल, यशपाल प्रजापति, निधि मोहन, गोपाल सैनी आदि मौजूद रहे।

आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक बैंकों द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय योजनाओं के लिए चलाया जाएगा संतुष्टि अभियान: एडीसी दीपक बाबू लाल करवा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि हरियाणा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक वित्तीय योजनाओं के लिए संतुष्टि अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजनाओं के तहत रि-वेरिफिकेशन कार्य, इन योजनाओं से नए लोगों को शामिल करने तथा नए अकाउंट खोलने आदि कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होंगे। एडीसी दीपक बाबू लाल



करवा बुधवार को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैंकर्स द्वारा वित्तीय योजनाओं के लिए चलाए जाने वाले संतुष्टि अभियान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले हरियाणा एसएलबीसी कन्वीनर ललित

तनेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करें कि वे इस अभियान के तहत लगाए

जाने वाले शिविरों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं।

बैंकों द्वारा दी जाने वाली स्कीमों का पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कीमों से जुड़ने के लिए जागरूक करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देश भी जारी किए कि वे शिविरों के

प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए 1961 आवेदन, 445 किए सत्यापित, 1154 की जांच जारी-डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत नगर निगम कार्यालय में 1961 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 445 आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं, जबकि 1154 आवेदनों की जांच की जा रही है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के बाद सम्बंधित व्यक्ति को फोन करके ऑफलाईन माध्यम से नेहरू पैलैस स्थित कार्यालय में वैध मलकियत के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा जाता है, ताकि सम्बंधित फाईल को सत्यापन के लिए वार्ड जे.ई. के पास भेजी जा सके। उन्होंने आवेदनकर्ताओं से अपील करते कहा कि वह जल्द से जल्द अपने मालिकाना कागजात कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनकी फाईल को सत्यापित कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी जा सके।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदनकर्ताओं के मकान नगर निगम के लाल डोरा क्षेत्र में आते हैं, वह सम्पत्ति कर शाखा से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर उसे नेहरू पैलैस कार्यालय में जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अपना कच्चा मकान है और वह नगर निगम के वैध क्षेत्र में आता है तथा उसके पास मलकियत के वैध दस्तावेज हैं, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में अटल सेवा केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी आवेदनकर्ता के पास मलकियत का सबूत या निधि रजिस्ट्री, हस्तांतरण विलेख, जमाबंदी या इंतकाल जैसे मलकियत के दस्तावेज नहीं होंगे और प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र से बाहर होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के दौरान

आयोजन हेतु जिला स्तर पर शेडयूल तैयार करें। उन्होंने कहा कि 26 जून को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। इसमें डीडीएम नाबाई, डीडीपीओ, जिला परिषद सीईओ, बैंकों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डीडीपीओ कंवर दामन, एलडीएम एसके नंदा के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।



पाया गया है कि काफी लोगों के प्लॉट नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर व मलकियत के वैध दस्तावेज न होने के कारण 362 लोगों के आवेदन रद्द किए गए हैं।

निगमायुक्त ने बताया कि इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें केवल बीपीएल ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी अटल सेवा केन्द्र से आवेदन कर सकता है। इन योजनाओं के उचित मालिकाना कागजात कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनकी फाईल को सत्यापित कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी जा सके।

इसके अतिरिक्त प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास वैध मालिकाना सबूत भी होने चाहिए। वह व्यक्ति योजना के तहत अपने घर का निर्माण करने के पात्र होंगे।

परशुराम पहरावर धाम को मिलकर विकसित करेगा समाज: डॉ अरविंद शर्मा

संजना भारती संवाददाता कैथल। सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज मिलकर परशुराम पहरावर धाम को विकसित करेगा और भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा की स्थापना करेगा। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता व सर्व समाज के सहयोग से 30 मई को रोहतक के पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कोने-कोने, हर गांव, हर गली से विशाल जनसमूह उमड़ा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तीसरे कैपस में तीन शिक्षण संस्थानों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों शिलान्यास हुआ, जो प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक अवसर उपलब्ध करवाने में अहम योगदान देंगे।

बुधवार दोपहर ब्राह्मण धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के तत्वावधान में प्रदेश के सभी जिलों के ब्राह्मण संगठनों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों द्वारा सुरेंद्र शर्मा बड़ौता व विजय शर्मा विक्की की अगुवाई में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा का जोरदार अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए फरसा भेंट किया गया। मंत्री ने ब्राह्मण धर्मशाला में विकास कार्य के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तीसरे कैपस में पांच शिलान्यास होने से 50 साल बाद शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने



कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ, भगवान परशुराम नर्सिंग कालेज फार गर्ल्स, गौड़ संस्था के प्रशासनिक भवन व भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि गौड़ संस्था से लाखों परिवार की आत्मा जुड़ी हुई है। देश की प्रख्यात संस्थाओं में एक गौड़ संस्था के तीसरे कैपस को भगवान परशुराम पहरावर धाम के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया गया है, जिसे सर्व समाज की भागीदारी के साथ सिरि चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान राजा भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राजकीय अवकाश की परंपरा शुरू हुई। भिवानी में 538 करोड़ रुपये की लागत से पण्डित नेकीराम शर्मा

मेडिकल कालेज का निर्माण पूरा हुआ, वहीं कैथल के सांपन खेड़ी में भगवान परशुराम जी के नाम से एक हजार करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हमें एकजुट होकर काम करना है, क्योंकि जितना ब्राह्मण समाज एकजुट होगा, उतना समाज को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही गौड़ संस्था की सदस्यता की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें आप सब अपनी भागीदारी जरूर करें। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग, राजकुमार शर्मा, विजय शर्मा, कुलदीप कौशिक, अजय कौशिक, रतन शर्मा, अर्जुन शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सुदामा शर्मा, नरेंद्र कौशिक समेत बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बरसात से गर्मी में मिली राहत, धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार: गुरजीत सिंह

■ बिना बरसात बौने पड़ रहे थे सिंचाई के लिए किसानों के संसाधन



एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग असंध। क्षेत्र में बुधवार की सुबह हुई लाम्भग एक घंटा तेज बरसात से जहां एक ओर किसानों के चेहरे खिले हैं वहीं धान की रोपाईं ने रफ्तार पकड़ ली है। जलमाना सहित आस पास के किसान गुरजीत सिंह शेखुपुरा, परमजीत सिंह खारा,परसेम सिंह खारा, हिमंत सिंह, नरेंद्र सिंह, बूटा सिंह, गुजेंद्र सिंह पहलवान, गुरवंत सिंह संधु शेखुपुरा, राजेश जून कुरलन का कहना है कि धान रोपाई के ठीक मौके पर हुई तेज बरसात से धान की फसल को संजीवनी मिलेगी, इससे धान एवं गन्ने की फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। इसके साथ ही एक दिन पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से

भी किसानों को खुशी मिली है। आमजन के लिए भी मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, 15 जून से अब तक हुई धान की रोपाई धान की रोपाईं ने रफ्तार पकड़ ली है। बारिश न होने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार अल सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला।

आसमान में बादलों ने करवट ली और झमझम बारिश शुरू हो गई। इससे पहले फसलों की सिंचाई के लिए किसान खुद के संसाधनों पर निर्भर थे जो खेतों की सिंचाई के लिए नाकाफी थे। जलमाना, उपलाना, उपलानी, चोरकारसा, ठरवा माजरा, ठरी, कुरलर,

अलाबला, शेखुपुरा मंचूरी सहित आस पास के इलाके में तेज बारिश हुई। जिसपर सरपंच सरबरी दहिया, लाला कैलाश गोयल, रमेश गोयल, किरण प्रजापत, सतबीर सिंहमार, डॉ सुरेंद्र नेगल, डॉ विक्की, राजेंद्र जोहल, बलवान सिंह, राजेश राठी आदि ने प्रसन्नता जाहिर की। उनका कहना है कि बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धान की फसल को फायदा पहुंचा है।

इस अवसर पर जलमाना में बच्चों व किशोरों ने भीगकर बारिश का लुटफ उठाया। खेतों में पानी भर गया है। धान रोपाई करने वाले श्रमिकों को भी राहत मिली है।

डीसी प्रीति ने ली ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक



संजना भारती संवाददाता कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद, डीडीपीओ, एस&ईन पंचायती राज व बीडीपीओ कार्यालय आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें। इन विभागों के विभागाध्यक्ष योजनाओं की लगातार माॉनटरिंग सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरपंच गंभीरता से कार्य करें। यदि कोई सरपंच लापरवाही बरतता है तो उसे नोटिस जारी कर दिया जाए। डीसी ने काम में लापरवाही बरतने पर दो एबीपीओ को नोटिस जारी करने की भी निर्देश दिए। डीसी प्रीति ने जिले में ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक में उक्त आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाए

और सभी की हाजरी शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में विकास काज होगा, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के तहत आजीविका मिलेगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बीडीपीओ एस&ईपीओ को भी साथ लें और कार्य को गंभीरता से करवाएं। विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण करें। अमृत सरोवर में के तहत तालाबों का निरीक्षण कर लंबित कार्य को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सांसद निधि योजना के तहत बनने वाले जिम सहित अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गंभीरता से कार्य करने के आदेश जारी किए और तथ्यों का प्रस्तुतीकरण यथार्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिनको पहली किशत जारी की जा चुकी है, तो उनकी दूसरी किस्त में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कहा कि सरपंच सफाई कार्य की निगरानी करें। बीडीपीओ, डीडीपीओ गांवों में सफ-

सफाई का औचक निरीक्षण करते रहें। इस कार्य में कोताही सहन नहीं होगी। बीडीपीओ गंभीरता से कार्य करें। यदि कोई सरपंच साफ-सफाई करवाने में लापरवाही बरतता है तो उसे नोटिस जारी करें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश देते हुए कहा कि बीडीपीओ सिंचाई विभाग की ड्रेनों की सफाई की जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। ठोस कचरा प्रबंधन योजनाओं को लेकर जमीनी स्तर पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम, गोबर्धन, जनसंवाद, सीएम विंडो, ई-लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हुए कार्यों की समीक्षा की।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डिप्टी सीईओ रिंतु लाउठर, डीडीपीओ कंवर दामन, कार्यकारी अधिकारी नारायणदत्त के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

टी.बी. उन्मूलन की दिशा में एक और कदम: करनाल में अत्याधुनिक अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने सिविल सर्जन कार्यालय में मेदांता फाउंडेशन द्वारा भेंट की गई आधुनिक अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ. चौधरी ने फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है, जो मात्र 2-3 मिनट में एक्स-रे रिपोर्ट प्रदान कर सकती है। इस मशीन का उपयोग मेदांता फाउंडेशन के स्टफ और स्वास्थ्य विभाग की

टीमें गांव-गांव जाकर संचालित टी.बी. मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए करेंगी ताकि उन्हें समय रहते इलाज मिल सके। उप-सिविल सर्जन (टी.बी.) डॉ. सिम्मी कपूर ने बताया कि टी.बी. एक संक्रामक रोग है जो मरीज के छांसने या छींकने से फैलता है। उन्होंने बताया कि मेदांता फाउंडेशन पूर्व में भी एक मोबाइल क्लीनिक वैन उपलब्ध करा चुका है जिसमें एक्स-रे व सीबीनाट की सुविधा है और यह वैन लगातार ग्रामीण व उच्च जोरिम वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कार्य कर रही है। डॉ. कपूर ने बताया कि टी.बी. के लक्षणों

में दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना, सांस लेने में परेशानी, भूख न लगना, रात को पसीना आना, थकावट, सीने में दर्द और बलगम में खून आना शामिल हैं। इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में टी.बी. के मरीजों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और सरकार ने इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जिसके तहत सभी जोरिम वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कार्य कर रही है। डॉ. कपूर ने बताया कि टी.बी. के लक्षणों